पेज थ्री
देहरादून

पुस्तक मेले के उद्घाटन अवसर पर संजीव कुमार शर्मा।

देहरादून, शनिवार 30 नवंबर, 2019

पेज 8

हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

अपीलों, शिकायतों की सुनवाई की तिथि परिवर्तित

संवाददाता देहरादून। उप सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने अवगत कराया है कि मुख्य सूचना आयुक्त की पीठ में 02 दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक योजित द्वितीय अपीलों, शिकायतों की सुनवाई की तिथि परिवर्तित की गयी है। उन्होंने अवगत कराया है कि 02 दिसम्बर की सुनवाई 24 जनवरी 2020, 03 दिसम्बर की सुनवाई 27 जनवरी 2020, 04 दिसम्बर की सुनवाई 07 जनवरी 2020, 05 दिसम्बर की सुनवाई 29 जनवरी, 06 दिसम्बर की सुनवाई 30 जनवरी, 09 दिसम्बर की सुनवाई 31 जनवरी तथा 10 दिसम्बर को योजित सुनवाई 04 फरवरी 2020 को की जायेगी।

श्रम मंत्री करेंगे योजनाओं का शुभारम्भ

संवाददाता देहरादून। श्रममंत्री उत्तराखण्ड सरकार डॉ हरक सिंह रावत आगामी 30 नवम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे आईआरडीटी ऑडिटोरियम (प्रेक्षागृह) सर्वेचौक देहरादून में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं लघु व्यापारी एनपीएस योजना के कैम्प का शुभारम्भ करेंगे।

वेल्हम बॉयज स्कूल में पुस्तक मेले का आयोजन

संवाददाता देहरादून। वेल्हम बॉयज स्कूल में पुस्तक मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के साहित्यकार, कवि एवं फिल्म फिल्म समीक्षक संजीव कुमार शर्मा ने किया। बतौर मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने अध्यापकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र एवं युवा पीढ़ी किसी भी विद्यालय, समाज एवं सभ्यता का निर्माण करते हैं। युवा पीढ़ी का साहित्य के प्रति जागरूक रहना एवं साहित्य निर्माण में सकारात्मक भूमिका का दीवाना अत्यंत आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि वेल्हम बॉयज स्कूल जैसी महान शैक्षिक संस्थाएं इसमें बहुत ही बेहतर योगदान दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर पुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण विद्यालय होती है। बस हमें उसकी गहराइयों तक उतरना होता है।

काम पर लौटे शुगर मिल के हड़ताली कर्मचारी

ऋषिकेश। वेतन की मांग को लेकर तीन दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे मिल के 600 कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है। कर्मचारियों को एक माह का वेतन और दो साल के ओवरटाइम का पैसा दिया जा चुका है। दरअसल, 28 नवंबर को डोइवाला शुगर मिल में पेराई सत्र के उद्घाटन के लिए प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान यशपाल आर्य को भी हड़ताली कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ा था।

मुख्यमंत्री ने कैडेटों को किया सम्मानित

कार्यक्रम

- एनसीसी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

देहरादून। **संवाददाता**

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को घंघोड़ा, देहरादून में एन.सी.सी स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग चौपिंयनशिप, नौकायन स्पर्धा जीतने वाले कैडेटों एवं बैण्ड कम्पीटिशन में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने एन.सी.सी की वार्षिक पत्रिका 'संकल्प' का विमोचन भी किया।

एनसीसी कैडेटों को सम्मानित करते सीएम।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एन.सी.सी का उद्देश्य केवल सेना में जाने के लिए ही नहीं है, बल्कि एकता, अनुशासन व समन्वय के साथ कार्य करने की प्रेरणा इससे मिलती है। एन.सी.सी प्रशिक्षण में सांस्कारिक भाव विकसित होते हैं, जिसमें कैडेट में अपनत्व का भाव विकसित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अनुशासित शक्ति के रूप में एन.सी.सी हमारे पास है, जिसका उपयोग समय–समय पर आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में एन.सी.सी की एक बटालियन खोलने के लिये संस्तुति दी गई है। उत्तराखण्ड के सीमांत जिलों चमोली एवं पिथौरागढ़ में भी एन.सी.सी बटालियन खोलने के लिए प्रयास किये जायेंगे। यह सौभाग्य की बात है कि गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखण्ड का एन.सी.सी बैण्ड को प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा।

अपर महानिदेशक एन.सी.सी मेजर जनरल सुधीर बहल ने कहा कि एन.सी.सी रक्षा सेवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए लाभकारी है। हमारे कैटेड ने अपने कौशल से उत्तराखण्ड का मान बढ़ाया है।

श्रीनगर में बनने वाले नये बस अड्डे के संबंध में बैठक

संवाददाता देहरादून। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में श्रीनगर में बनने वाले नये बस अड्डे के संबंध में आवास विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में काफी समय से नये बस अड्डे के निर्माण की मांग की जा रही है। पिछली सरकार ने इस बस अड्डे को पीपीपी मोड़ में देने की बात कही थी। लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण एनजीटी द्वारा नदी से 100 मीटर दूरी तक कोई भी स्थाई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सारी चीजों का अध्ययन कर एनजीटी के सम्बन्ध में जो भी समस्या होगी उस विषय पर आवास विभाग कोर्ट में अपना विषय रखेगा।

भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता पर होगी कार्रवाई: सीएम

समीक्षा

हर दस दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश, विभागीय सचिवों की होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चत हो

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विभागों में भर्ती के लिए संबंधित सचिवों की जिम्मेवारी तय करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट हर दस दिन में सचिव कार्मिक को उपलब्ध करवाई जाए। सचिव कार्मिक सभी विभागों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित करते हुए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री सचिवालय में सरकारी विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे।

विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते सीएम।

मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों व इन्हें भरने के लिए की गई कार्यवाही का पूरा विवरण उपलब्ध न करवाने वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें जल्द से जल्द निर्धारित प्रारूप में विवरण कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिक्त पदों पर भर्ती जल्द से जल्द करवाना चाहती है। ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और कर्मचारियों के अभाव में विकास के कार्य बाधित न हों। इसमें किसी तरह की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी। औपचारिकताओं को पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाए। मुख्यमंत्री ने शासन स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए जो कि विभागों में रिक्त पदों की स्थिति व इन्हें भरने के लिए की जा रही कार्यवाही की लगातार मॉनिटरिंग करेगी। विभागों द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचनों में कोई कमी न रहे, इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग व अधिनस्थ सेवा चयन आयोग से समन्वय कर, कमियों को अविलम्ब दूर करना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित आयोग को अधियाचन जल्द से जल्द भेजा जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के समान प्रकृति के पदों को भरने की प्रक्रिया यथासम्भव एक साथ सम्पन्न की जाए। इससे आवेदकों को बार–बार आवेदन करने से राहत मिलेगी। फील्ड कर्मचारियों की कमी को दूर करने को विशेष प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य लोक सेवा आयोग व अधिनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती प्रक्रिया में और तेजी लाने की अपेक्षा की। आयोग को इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होने पर शासन को अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष काम कर रहे उपनल, पीआरडी व अन्य संविदाकर्मियों का विवरण भी कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाया जाए। लम्बे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान दिया जाए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आनन्द सिंह रावत ने बताया गया कि वर्तमान में कोई भी अधियाचन लम्बित नहीं है।

'6 करोड़ 87 लाख के श्रण वितरण प्रस्ताव किये गये स्वीकृत'

संवाददाता देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में गठित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जिला टास्कफोर्स समिति की 28 एवं 29 नवम्बर को समन्वय बैठक में कुल 87 परियोजनाओं में 687.09 लाख के श्रण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

इस दौरान महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र शिखर सक्सेना द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं में कुल 128 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 26 आवेदक अनुपस्थित रहे और 15 आवेदन विभिन्न कारणों के चलते निरस्त हुए। योजना के अन्तर्गत उद्योग केन्द्र के 70 परियोजनाओं के साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 39 परियोजनाओं ने सापेक्ष रू0 374.59 लाख की स्वीकृति हुई, इसी प्रकार खादी ग्रामोद्योग आयोग की 32 परियोजनाएं साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत की गयी, जिसमें 25 के सापेक्ष रू0 178.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 26 परियोजनाएं साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत की गयी, जिसमें से 23 परियोजनाओं के सापेक्ष रू0 134.50 लाख की स्वीकृति प्रदान करने सभी बैकों को ऑनलाईन प्रेषित किये गये।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।